कानपुर, शनिवार, 10 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 14, पृष्ठः 8+4
प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी
सच्चाई के दम पर जोश के साथ...
www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत...>Pg12
तीन कथित पत्रकारों पर एफआईआर ... > Pg03

मूल्यः 2 ₹

कानपुर को जल्द मिलेगा 3000 करोड़ का गंगा पथ

8 किमी फोरलेन परियोजना को मिली हरी झंडी, मेगा योजना से बदलेगा पर्यटन नक्शा

प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के विकास को नई रफ्तार देने वाली गंगापथ परियोजना को शासन से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अटल घाट से शुक्लागंज स्थित पुराने गंगापुल तक प्रस्तावित करीब 8 किलोमीटर लंबे फोरलेन गंगापथ पर लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना न केवल शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करेगी, बल्कि गंगा किनारे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी।

परियोजना की डीपीआर तैयार कराने के लिए 27 जनवरी को टेंडर प्रक्रिया फाइनल की जाएगी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। शुक्रवार को सांसद रमेश अवस्थी के नेतृत्व में सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने गंगा में स्टीमर से निरीक्षण कर प्रस्तावित कॉरिडोर का जमीनी आकलन किया।

निरीक्षण के दौरान अटल घाट, सरसैया घाट, रानीघाट, भैरोघाट, परमट घाट से लेकर पुराने गंगापुल तक पूरे रूट का जायजा लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना पटना के गंगापथ की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिससे कानपुर को आधुनिक रिवर फ्रंट और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी।

कानपुर के विकास की रीढ़ बनेगा

सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि गंगापथ कानपुर के विकास की रीढ़ बनेगा, इससे यातायात सुगम होगा, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और शहर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।

राम जन्मभूमि परिसर में नमाज़ पढ़ने का प्रयास करते तीन संदिग्ध हिरासत में

➪ तीनों ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब तीन संदिग्ध व्यक्ति परिसर के भीतर घुस आए और नमाज़ पढ़ने का प्रयास करने लगे। सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो युवकों और एक युवती को हिरासत में ले लिया।

जानकारी के अनुसार, तीनों राम मंदिर के गेट ष्ठ-1 से परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद सीता रसोई के समीप एक युवक नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गया। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जैसे ही यह देखा, तुरंत उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तीनों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थीं। रोके जाने पर युवकों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से किसी भी अप्रिय स्थिति को टाल दिया गया। हिरासत में लिए गए एक युवक की पहचान अबू अहमद शेख, निवासी शोपियां (कश्मीर) के रूप में बताई जा रही है। पकड़ी गई युवती का नाम सोफिया बताया गया है, जबकि तीसरे युवक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

तीनों ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल, इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने भी चुप्पी साध रखी है।

माघ मेले के बीच प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी

त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी

संगम स्नान के बाद माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण, कल्पवासियों की सुविधाओं पर दिए सख्त निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को माघ मेले के पावन अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। आध्यात्मिक वातावरण के बीच उन्होंने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। स्नान के उपरांत मुख्यमंत्री ने मां गंगा का पूजन-अर्चन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री के संगम आगमन से माघ मेले में मौजूद श्रद्धालुओं, संत-महात्माओं और कल्पवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे और संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गंगा पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टीमर के माध्यम से माघ मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक भावनात्मक और मनोहारी दृश्य उस समय देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ने संगम तट पर दूर-दराज से आए साइबेरियन पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाया। जल में दाना डालते ही विदेशी पक्षियों का झुंड स्टीमर के चारों ओर मंडराने लगा, जिसे देखकर मौके पर मौजूद श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, विशेष रूप से कल्पवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। घाटों की नियमित सफाई, गंगा जल की निर्मलता,

पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। संगम से वह सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे, जहां जगदगुरु रामानंदाचार्य की जयंती समारोह में उन्होंने सहभागिता की। इस अवसर पर 51 बटुकों द्वारा पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करेंगे और वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

सार्वजनिक भूमि संरक्षण, महिला सशक्तिकरण व स्वास्थ्य योजनाओं पर दिया विशेष जोर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग एवं नोडल अधिकारी जनपद कानपुर देहात जी.एस. प्रियदर्शी की अध्यक्षता में विकास खंड मलासा के ग्राम कछगांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर लाभ वितरण की गहन समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी ने विभागवार योजनाओं की जानकारी लेते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान पाइपलाइन लीकेज और रोड रेस्टोरेशन कार्य में अनियमितताओं की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए।

आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की मांग पर नोडल अधिकारी ने आवास प्लस सर्वे में शामिल सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए।

साथ ही ग्राम में स्थित तालाबों, चारागाहों, रास्तों, पंचायत भूमि व अन्य सार्वजनिक भूमि के चिन्हांकन और संरक्षण पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा में समूहों की संख्या बढ़ाने, महिलाओं को अधिक से अधिक समूहों से जोड़ने, बैंक लिंकेज और आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। राशन कार्ड व राशन वितरण से जुड़ी शिकायतों पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। शीतलहर को देखते हुए जरूरतमंद ग्रामीणों को कंबल वितरण किया गया। निराश्रितों व वृद्धजनों को पेंशन योजनाओं से जोड़ने तथा निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में संरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया गया।

गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं शिशुओं का अन्नप्राशन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसके बाद नोडल अधिकारी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ग्राम चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह, डीएफओ ए.के. पाण्डेय, अपर जिलाधिकारीगण, जिला स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सोते रहे परिजन, नगदी समेत लाखों के जेवरात ले उड़े चोर

महमूदापुर खुर्द गांव में घर को बनाया निशाना, पुलिस जांच में जुटी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के महमूदापुर खुर्द गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान घर के सभी सदस्य एक ही कमरे में सोते रहे और उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी।पीड़ित गुफरान निवासी महमूदापुर खुर्द ने बताया कि अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में घर के दूसरे कमरे की कुंडी खोलकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी और बक्सों के ताले तोड़ दिए गए। चोर अलमारी में रखे करीब 10 हजार रुपये नकद के साथ-साथ सोने-चांदी के कीमती जेवरात चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

सुबह जब परिजन जागे तो कमरे में बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में इसकी सूचना डेरापुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि चोरी की घटना को गंभीरता से लिया गया है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गांव में हुई इस वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।

नगर निगम क्षेत्र में बंदर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा निर्णय

वन विभाग शहरी क्षेत्र में पकड़ेगा बंदर, डीएफओ को भेजी जाएंगी नगर निगम में आने वाली शिकायतें

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर/लखनऊ।नगर निगम कानपुर क्षेत्र में लंबे समय से गंभीर बनी बंदर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका संख्या 1030/2025 के आदेश दिनांक 03 दिसम्बर 2025 के अनुपालन में 08 जनवरी 2026 को शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में बंदरों की लगातार बढ़ती संख्या, उनसे उत्पन्न जनसुरक्षा की समस्याएं, सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव तथा मानव-बंदर संघर्ष के विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।बैठक में बंदरों को पकड़ने, उनके पुनर्वास तथा वैज्ञानिक और मानवीय प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं

नगर निगम सीमा के अंतर्गत बंदरों को पकड़ने की संपूर्ण कार्यवाही अब वन विभाग द्वारा की जाएगी।

नगर निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बंदर पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।बंदरों को पकड़ने, उनके परिवहन, पुनर्वास एवं समग्र प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन संपादित किए जाएंगे।यह कार्यवाही भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानव-बंदर संघर्ष निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, वैज्ञानिक, मानवीय और विधिसम्मत तरीके से की जाएगी।नगर निगम कानपुर द्वारा वन विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा बंदर-प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर स्थानीय स्तर पर समन्वय किया जाएगा।बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि शहरी इलाकों में बंदरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए उनका व्यवस्थित, सुरक्षित और स्थायी समाधान आवश्यक है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।इस निर्णय के बाद नगर निगम कानपुर क्षेत्र में बंदरों के आतंक से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और भविष्य में इस समस्या का समाधान एक सुव्यवस्थित और प्रभावी प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा।

निजीकरण और वेतन देरी पर आंदोलन को तैयार कर्मचारी

मीटिंग के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने बनाया संयुक्त मोर्चा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम प्रशासन की नीतियों के खिलाफ नगर निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। दिनांक 9 जनवरी 26 को नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित पार्क में कर्मचारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था, रविस विभाग की गाड़ियों, कूड़ा कलेक्शन सहित कई सेवाओं को निजीकरण के तहत टेंडर पर देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया गया।

बैठक में सफाई कर्मचारियों की सुबह 5 बजे ड्यूटी तय करने, फेस अटेंडेंस लागू करने और प्रत्येक माह 5 तारीख तक वेतन न मिलने जैसे गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। कर्मचारियों ने इन समस्याओं को लेकर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के गठन का ऐलान किया। तय किया गया कि सभी संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री संयुक्त रूप से आंदोलन का संचालन करेंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सबसे पहले नगर आयुक्त को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर वार्ता का समय मांगा जाएगा और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और समाधान नहीं निकला, तो वे विवश होकर आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता किशनलाल सुदर्शन ने की, जबकि संचालन रमाकांत मिश्र ने किया। बैठक में हरिओम वाल्मीकि, सी एल बड़ेल, मुन्ना हजारिया, उस्मान अली, राहुल भारती, पिंटू चौधरी, मोरध्वज वाल्मीकि, रमेश चंद्र शुक्ला, कमरुद्दीन, हरिशंकर शुक्ला, सुमिंद्र कुमार, आदेश शुक्ला, धीरज वाल्मीकि, नरेश सागर, मुकेश कुमार, जयपाल सिंह, सतीश कुमार, मुन्ना गंगोत्री सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।

बैठक के समापन पर नगर निगम मुख्यालय के सामने कर्मचारियों और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी एकजुटता और संघर्ष के इरादे का प्रदर्शन किया।

फर्जी खबरों के दबाव का आरोप तीन कथित पत्रकारों पर FIR

स्वराज इंडिया न्यूज

➪ निजी अस्पताल संचालक ने शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन

कानपुर। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के बिठूर नगर में संचालित एक निजी अस्पताल को कथित रूप से बदनाम करने और दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने तीन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अस्पताल संचालक की शिकायत पर दर्ज इस एफआईआर के बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है।

अस्पताल संचालक सौरभ वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में निजी अस्पताल का संचालन कर रहे हैं और अब तक उनकी छवि साफ रही है। आरोप है कि पत्रकार मनोज शुक्ला, मुकेश यादव और मनीष गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्पताल के खिलाफ झूठी, भ्रामक और तथ्यों से परे खबरें व वीडियो प्रसारित किए। इन खबरों में अस्पताल पर अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए गए, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल बन गया।

शिकायत में कहा गया है कि इन खबरों के जरिए अस्पताल को बदनाम करने के साथ-साथ उसे बंद कराने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप यह भी है कि तीनों पत्रकार लगातार अस्पताल संचालक से संपर्क कर अपने पक्ष में समझौता करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा न करने पर नकारात्मक खबरें और तेज करने की धमकी दी जा रही थी।

अस्पताल संचालक का कहना है कि फर्जी खबरों के कारण अस्पताल की साख को नुकसान पहुंचा है और मरीजों की संख्या पर भी इसका असर पड़ा है। इसी से आहत होकर उन्होंने पुलिस की शरण ली और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री, वीडियो और पोस्ट की जांच की जा रही है। तथ्यों के सत्यापन के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को बदनाम करना या दबाव बनाना कानूनन अपराध है। मामले की जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

विक्रमशिला एक्सप्रेस से अपहृत एक वर्षीय बच्चे का रेस्क्यू, शातिर गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। दिल्ली पुलिस की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ कानपुर सेंट्रल ने गाड़ी संख्या 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस से अपहरण किए गए एक वर्षीय बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान अपहरण के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

आरपीएफ के मुताबिक 9 जनवरी 2026 को प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल एसएन. पाटीदार को दिल्ली पुलिस थाना कपसेरा (वेस्ट दिल्ली) से सूचना मिली कि हेमंत कुमार नामक व्यक्ति एक वर्षीय बच्चे का अपहरण कर दिल्ली से बिहार की ओर विक्रमशिला एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहा है।

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में उप निरीक्षक मो. असलम खान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में उप निरीक्षक नितिन कुमार, एएसआई राजेश सिंह, एएसआई सी.पी. सिंह, एएसआई जयप्रकाश पाठक सहित कुल आठ आरपीएफ कर्मी शामिल रहे। सभी कर्मियों को आरोपी और बच्चे की तस्वीरें दिखाकर ब्रीफ किया गया।

ट्रेन के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शाम 8:15 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते ही आगे और पीछे के जनरल कोचों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान आरोपी पीछे के जनरल कोच में बच्चे के साथ बैठा मिला।

आरपीएफ टीम ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमंत कुमार मंडल , निवासी विजलपुर, जिला भागलपुर (बिहार) के रूप में हुई है। बरामद बच्चे को 'मेरी सहेली' स्टाफ की निगरानी में सुरक्षित रखा गया।

कानपुर की आईजीआरएस रैंकिंग गिरी, 21 विभागों को नोटिस

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।आईजीआरएस में लगातार गिरती रैंकिंग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एडीएम सिटी ने जनपद के 21 विभागों को नोटिस जारी करते हुए शिकायतों के निस्तारण में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराज़गी जताई है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कई मामलों में नामित जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते निगेटिव फीडबैक मिल रहा है और

जनपद की रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है। प्रशासन का कहना है कि निगेटिव फीडबैक वाले विभागों को पूर्व में भी कई बार चेतावनी और नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस और व्यापक प्रयास नहीं किए गए।

एडीएम सिटी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन विभागों को भेजा गया नोटिस

खंड विकास अधिकारी कल्यानपुर, जिला उपायुक्त, स्वरोजगार परियोजना अधिकारी, नेडा, उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, सहायक श्रमायुक्त, अधिशासी अभियंता केस्को आईजीआरएस, नगर आयुक्त नगर निगम, अधिशासी अभियंता विद्युत, तहसीलदार बिल्हौर, उपजिलाधिकारी नर्वल, उपनिदेशक कृषि विभाग, अधीक्षण अभियंता केस्को आईजीआरएस, प्रभागीय वन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, उपजिलाधिकारी सदर।जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि आगे भी शिकायत निस्तारण में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सफाई कर्मचारियों से अभद्रता पर थाना घेरा

सेनेटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ ने आरोप लगाते हुए थाना अनवरगंज का किया घेराव

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सफाई अभियान के दौरान कर्मचारियों से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सेनेटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ ने गुरुवार को थाना अनवरगंज का घेराव किया। संघ के महामंत्री मो. उस्मान अली शाह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी थाने पहुंचे तथा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

संघ पदाधिकारियों के अनुसार, घटना 8 जनवरी 2026 की है। वार्ड संख्या 56 में चल रहे सफाई अभियान के दौरान क्षेत्र के दबंग अभिषेक पुत्र बलराज ने सफाई पर्यवेक्षक क्रिस्टी को बेवजह रोक लिया। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। साथ ही, लाखन नामक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई।

घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने संगठन के नेताओं के साथ थाना अनवरगंज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। घेराव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दुबे और चौकी प्रभारी शुक्ला ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया।

संघ की ओर से थाना अनवरगंज में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान थाने परिसर में संघ के सैकड़ों पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

10 क्षय रोग मरीज़ों को पोषण पोटली वितरित

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश टीबी मेल हेल्थ विजिटर्स संघ की ओर से जिला क्षय रोग विभाग परिसर में 10 क्षय रोग मरीज़ों को पोषण पोटली प्रदान की गई।

कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष सागर पाण्डेय ने किया।इस अवसर पर सागर पाण्डेय ने बताया कि क्षय रोग मरीज़ों को छह माह तक लगातार पोषण पोटली दी जाएगी। संघ लंबे समय से क्षय रोग मरीज़ों के उपचार और सहयोग के लिए कार्य कर रहा है और आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पोषण पोटली में भुना चना, गजक, मूंगफली का दाना, होर्लिक्स, सत्तू और गुड़ शामिल हैं।

जिनके सेवन से क्षय रोग मरीज़ों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश भर के सभी संघ पदाधिकारियों से अपने-अपने जनपदों में पोषण पोटली अभियान चलाने का आह्वान किया, ताकि कर्मचारियों और आम जनता को जागरूक कर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाया जा सके।पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला क्षय रोग अधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर सुबोध प्रकाश, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीबी सिंह, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाहकार डॉक्टर प्रीति, और मॉड्यूलर ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर की डॉक्टर रोहिणी यादव उपस्थित रहीं।इसके साथ ही चीफ फार्मासिस्ट गिरजेश पाण्डेय, लैब तकनीशियन अंजू सचान, सुधीर यादव, समसुद्दीन शेख, प्रेम शंकर, मेहन्द्र शर्मा, दुर्गेश प्रताप सिंह, आनंद पाण्डेय, वाहन चालक राजा कुशवाहा, नितिन सहित समस्त टीबी क्लिनिक कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।प्रदेश अध्यक्ष ने जिला क्षय रोग अधिकारी और उप जिला क्षय रोग अधिकारी का कार्यक्रम में समय देने और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

सम्पादकीय

इंदौर से सबक ले रोहतक को राहत दें

यह विडंबना ही है कि हमारे नागरिक प्रशासन का नियामक तंत्र आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता से मुक्त नहीं होता। यदि समय रहते संवेदनशील या फिर घातक साबित होने वाली स्थिति व परिस्थिति पर नजर रखी जाए तो जनधन की हानि टाली भी जा सकती है। हाल ही में दूषित पेयजल से इंदौर में हुई जन हानि के बाद रोहतक और झज्जर की उन चेतावनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती,जिसमें नागरिक घरों में आने वाले गंदे व बदबूदार पानी की शिकायत करते रहे हैं। निश्चय ही इस स्थिति को जन स्वास्थ्य से जुड़े आपातकाल के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों की शिकायत की जांच-पड़ताल कर अविलंब कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जवाबदेही न निभाने और एक-दूसरे विभाग पर दोष मढ़ने का पुराना सिलसिला ही अकसर सामने आता है। उल्लेखनीय है कि इंदौर की हालिया दूषित पेयजल की त्रासदी में नगरपालिका द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी के सेवन से कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विडंबना यह है कि वहां भी नागरिकों की शुरुआती चेतावनियों को सामान्य शिकायतों के रूप में देखकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इंदौर में पेयजल पाइपलाइनों में सीवेज का रिसाव हुआ था। यह स्वीकारोक्ति भी तब सामने आई जब बड़ा नुकसान हो चुका था। लगता है कि रोहतक व झज्जर भी इसी तरह के आसन्न खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आने वाले ऐसे मामले न तो रहस्यमय हैं और न ही ये कोई नई बात ही है। बुनियादी ढांचागत व्यवस्था का जर्जर होना, सीवर लाइनों में रिसाव, अनियोजित शहरी विस्तार और नागरिक एजेंसियों के बीच आवश्यक समन्वय का अभाव, अकसर ऐसी स्थिति पैदा कर देता है, जहां सीवेज और पीने का पानी खतरनाक रूप से एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं।

गाहे-बगाहे देश के विभिन्न भागों में स्थानीय नागरिक जब-तब आरोप लगाते हैं कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिलने की आशंका है। ऐसे में शासन-प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया, इसके सत्यापन, पाइप लाइन की मरम्मत और वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य संकट को दूर करने और अपनी बात मनवाने के लिये यदि नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ता है तो यह शासन-प्रशासन की विफलता को ही दर्शाता है। विडंबना यह है कि जल प्रदूषण का सबसे बुरा असर समाज के कमजोर वर्ग पर ही पड़ता है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इसकी चपेट में आते हैं। निर्विवाद रूप से दूषित जल से डायरिया, हेपेटाइटिस और अन्य दूषित जल जनित बीमारियों का प्रभाव तेजी से फैलता है। जिसके चलते अफरा-तफरी के बीच अक्सर स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में तंत्र की निष्क्रियता की कीमत आम लोगों को न केवल अस्पताल के भारी-भरकम बिलों के रूप में, बल्कि जानमाल के नुकसान और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास में आई कमी के रूप में भी चुकानी पड़ती है। निश्चित रूप से दूषित पाइपलाइनों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए।

व्यापक स्तर पर प्रभावित क्षेत्र में जल स्रोतों का परीक्षण होना चाहिए।

कॉपीराइट कंटेंट के दुरुपयोग का सवाल

यशवंत सचदेव

एआई कंपनियां कॉपीराइट वाले कंटेंट के उपयोग से एलएलएम मॉडल प्रशिक्षित कर बिजनेस कर रही हैं जो सवालों के घेरे में है। बेशक एलएलएम व अन्य मॉडल तकनीकी नवोन्मेष का नतीजा है, लेकिन यह दशकों से लाखों रचनाकारों द्वारा निर्मित...एआई कंपनियां कॉपीराइट वाले कंटेंट के उपयोग से एलएलएम मॉडल प्रशिक्षित कर बिजनेस कर रही हैं जो सवालों के घेरे में है। बेशक एलएलएम व अन्य मॉडल तकनीकी नवोन्मेष का नतीजा है, लेकिन यह दशकों से लाखों रचनाकारों द्वारा निर्मित काम की डिजिटल चोरी पर टिका है। प्रस्तावित कॉपीराइट फ्रेमवर्क में रचनाकारों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे ही साल खत्म हो रहा था, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 'जेनरेटिव एआई एंड कॉपीराइट' पर एक कार्यपत्र प्रकाशित किया।

यह अप्रैल, 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कॉपीराइट सुरक्षा के जटिल सवाल की जांच के लिए गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है, और इसके निष्कर्षों से निकट भविष्य में कॉपीराइट और जेनरेटिव एआई के संबंध में भारत की आधिकारिक नीति का आधार बनने की सर्वाधिक संभावना है। जेनरेटिव एआई उत्पाद जैसे कि चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी इत्यादि लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) हैं, जो यूजर्स द्वारा दिए गए प्रॉम्पट्स (निर्देश) के आधार पर कंटेंट उत्पन्न करके देते हैं। मसलन, कोई व्यक्ति चैट जीपीटी को कहे कि आरके नारायण या मुंशी प्रेमचंद की शैली में एक लघु कहानी लिखकर दो, और वह उसे उत्पन्न कर दे। इसी तरह, डाल-ई, मिडजर्नी (और इस जैसे टेक्स्ट-टू-इमेज और टेक्स्ट-टू-वीडियो जेनरेशन मॉडल) दिए गए विषय पर पेंटिंग बनाकर पेश कर सकते हैं, जिसके लिए निर्देश दिए जाएं कि इनकी शैली जैमिनी रॉय या एमएफ हुसैन जैसी हो। या फिर सत्यजीत रे की शैली में एक लघु फिल्म क्लिप बनाने को कहा जाए। जेनरेटिव एआई मॉडल से उत्पन्न होने वाली सामग्री उनके प्रशिक्षण पर आधारित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्रोत (जैसे नारायण के उपन्यास या हुसैन और अन्य की पेंटिंग) से प्राप्त डेटा का उपयोग किया जाता है। एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा विभिन्न श्रेणियों वाला हो सकता है- कॉपीराइटेड, कॉपीराइट-समाप्त और सार्वजनिक डोमेन में 'उचित उपयोग' की अनुमति वाला उपलब्ध डेटा। जब से प्रौद्योगिकी फर्मों ने जेनरेटिव एआई उत्पादों के व्यावसायिक संस्करण लॉन्च किए हैं, किताबों, शोधपत्रों, तस्वीरों, फिल्मों और रचनात्मक अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों जैसी कॉपीराइटेड सामग्री में उनके उपयोग का सवाल एआई बहस का केंद्र बन गया है। इसने जटिल कानूनी, नैतिक और औचित्य संबंधी प्रश्न खड़े कर दिए। एक और अनसुलझा मुद्दा एआई-जनित आउटपुट की कॉपीराइट-योग्यता और लेखक का अधिकार है।कई देशों में सरकारें और अदालतें इस नए चलन -एआई मॉडल का डेटा प्रशिक्षण- से निपटने के लिए जूझ रही हैं। भारत सहित दुनियाभर की प्रौद्योगिकी कंपनियों की दलील है कि एआई मॉडल कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन नहीं करते क्योंकि वे कॉपीराइटेड किताबों, तस्वीरों आदि की नकल या साहित्यिक चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल अलग डेटासेट के रूप में एल्गोरिद्म को प्रशिक्षित करने के लिए पैटर्न, शैलियों, संरचनाओं का उपयोग करके सांख्यिकीय संबंध के संदर्भ में उन्हें नई सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम बनाने को कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह रचनात्मक कार्यों का 'उचित उपयोग' वाले सर्वमान्य सिद्धांत के अनुरूप है। यह तर्क देना कि एआई मॉडल मूल कामों की 'नकल' नहीं कर रहे, बल्कि उनसे सिर्फ़ 'सीख' रहे हैं, सही नहीं। क्योंकि एक एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिसमें डेटा (मूल सामग्री) की कॉपी करना और स्टोर करना शामिल हैं,। जो वस्तुतः कॉपीराइट का उल्लंघन है। जबकि एआई उद्योग का कहना है ।

संस्कृति और तकनीक के बीच सेतु बनी हिंदी

विश्व हिन्दी दिवस

डा0 सुधीर कुमार

शोध और नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम को प्रोत्साहन मिल रहा है। विज्ञान, पर्यावरण, तकनीक, सामाजिक अध्ययन और डेटा विश्लेषण जैसे विषयों पर हिन्दी में शोध कार्य सामने आ रहे हैं। यह ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है। हिन्दी केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और चेतना की एक जीवंत धारा है, जो इस देश की आत्मा को स्वर देती आई है। आज जब विश्व तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रहा है, हिन्दी भी खुद को नए संदर्भों में पुनः परिभाषित कर रही है। पहले केवल कविता, कथा और संवाद की भाषा मानी जाने वाली हिन्दी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान, डिजिटल नवाचार और वैश्विक संवाद की प्रभावशाली भाषा बनती जा रही है।

विश्व हिन्दी दिवस 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में हुए पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जिसने हिन्दी को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक मंच पर स्थापित किया। इस सम्मेलन के बाद, विभिन्न देशों में आयोजित अन्य विश्व हिन्दी सम्मेलनों ने यह सिद्ध किया कि हिन्दी अब केवल भारत की भाषा नहीं, बल्कि यह विश्वभर में सांस्कृतिक पहचान और संवाद का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। आज, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हिन्दी बोलने वाले समुदाय न केवल हिन्दी साहित्य से जुड़े हैं, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी हिन्दी के उपयोग

को बढ़ावा दे रहे हैं।

इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह वह तकनीक है, जिसने मानव और मशीन के संबंधों को नई परिभाषा दी है। एआई अब केवल गणना करने वाली मशीन नहीं, बल्कि भाषा समझने, संवाद करने, निर्णय लेने और रचनात्मक कार्यों में भागीदारी निभाने वाली प्रणाली बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में हिन्दी ने इसमें सशक्त प्रवेश किया है। आज वैश्विक तकनीकी कंपनियां हिन्दी को गंभीरता से अपना रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट्स, वॉयस असिस्टेंट्स, ट्रांसलेशन टूल्स और कंटेंट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हिन्दी में संवाद करने लगे हैं। हिन्दी में प्रश्न पूछने पर हिन्दी में ही सटीक, संदर्भपूर्ण और सहज उत्तर मिलना अब असंभव नहीं रहा। यह केवल भाषा का अनुवाद नहीं, बल्कि भाषा की समझ का विकास है। मशीनें अब हिन्दी के व्याकरण, भाव, मुहावरों और यहां तक कि क्षेत्रीय लहजों को भी पहचानने लगी हैं। इससे तकनीक और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो रही है।हिन्दीभाषी समाज, अब डिजिटल अर्थव्यवस्था का सक्रिय भागीदार बन रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, प्रशासन और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में हिन्दी आधारित एआई टूल्स आम लोगों के जीवन को सरल बना रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर सरकारी योजनाओं की जानकारी, टेलीमेडिसिन से लेकर डिजिटल भुगतान तक, हिन्दी तकनीक का माध्यम बन रही है। यह परिवर्तन सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। विज्ञान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हिन्दी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्राथमिकता देकर इस बदलाव को गति दी है। आज इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, प्रबंधन और विज्ञान जैसे विषयों की अध्ययन सामग्री हिन्दी में उपलब्ध कराई जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिन्दी में विज्ञान और तकनीक से जुड़े पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर और अध्ययन सामग्री छात्रों के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। शोध और नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम को प्रोत्साहन मिल रहा है। विज्ञान, पर्यावरण, तकनीक, सामाजिक अध्ययन और डेटा विश्लेषण जैसे विषयों पर हिन्दी में शोध कार्य सामने आ रहे हैं।

नेवादा टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील के शिवराजपुर स्थित नेवादा टोल प्लाजा पर 37 वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के साथ की गई। 'सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा' को मूल मंत्र बनाकर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति सजग करना है।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने तेज रफ्तार, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया। मुख्य अतिथि ने कहा कि सड़क पर निकलने वाला हर व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ चलता है, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। नियमों की जानकारी होते हुए भी उनका पालन न करना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस अवसर पर आपात

- **'सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा' के संदेश के साथ**
- **जागरूकता कार्यक्रम के लिए दो एंबुलेंस रवाना**

स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए दो नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार जागरूकता व सख्त निगरानी की जाएगी।

यह कार्यक्रम जिलाधिकारी के निर्देशों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन और बिठूर कानपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। एनएचएआई के तकनीकी प्रबंधक, डीएसपी, आरटीओ सहित अनेक प्रशासनिक और यातायात अधिकारी मौजूद रहे।

परियोजना प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत पूरे माह विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें स्कूलों में प्रतियोगिताएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्रदर्शनियां शामिल होंगी।

कार्यक्रम का संचालन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अवार्ड से सम्मानित फिरोज़ खान ने किया। इस मौके पर एसीपी मंजय सिंह,इंस्पेक्टर बिल्हौर अशोक कुमार सरोज, अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन यादव, शिवराजपुर इंस्पेक्टर वरुण शर्मा समेत कई पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

हाइवे पर अंधेरा, सुरक्षा नदारद- जिम्मेदार कब जागेंगे?

बिल्हौर। टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा को लेकर भाषण और जागरूकता कार्यक्रम तो हो गया और फोटो भी खिंच गए। लेकिन बाईपास हाइवे की अवस्था पर कब बात होगी। जिस बाईपास को सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए बनाया गया, वही रात होते ही कई जगह अंधेरे में डूब जाता है और हादसों को खुला न्योता देता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बाईपास पर स्ट्रीट लाइटें गिनती की हैं, कई हिस्सों पर अंधेरा रहता है। और न ही पर्याप्त संकेतक हैं। नतीजा यह कि रात में वाहन चालकों को अंदाज़े से गाड़ी चलानी पड़ती है। कहां मोड़ है कहां कट यह भी समझ नहीं आता। सवाल यह भी है कि जब टोल पूरी सख्ती से वसूला जा रहा है, तो उसी अनुपात में सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं?

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब बाईपास और एक्सप्रेस-वे पर आवारा पशु बेखौफ घूमते नजर आते हैं। यह लापरवाही किसी भी दिन बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। और कई बड़े हदासे होते होते बचें भी हैं।ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? आमजन चाहता है कि कागज़ी कार्यक्रमों से आगे बढ़कर ज़मीनी सुधार हों, ताकि बाईपास सुरक्षित बने, न कि हादसों का।

एआईएमआई के नगर अध्यक्ष बनाए गए शहनवाज

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर कस्बे के एआईएमआई के कार्यकर्ता शहनवाज को पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और युवाओं में खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर युवाओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर बधाई दी। शहनवाज ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और

- **युवाओं ने फूल माला पहनाकर दी बधाई**

संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की अपील की। इस दौरान राजबाबू,अर्सलान बेग,सलीम खान मुन्ना, जावेद, हाशिम, आंनद समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

मेला गेस्ट हाउस के बाहर से हटवाए गए पशुओं के खूंटे

नायब तहसील ने निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। जिंदा शाह मदार की दरगाह पर लगने वाले सरकारी बसंत मेले को लेकर तहसील प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मेले की तैयारियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय लेखपाल ने मकनपुर में डेरा डालते हुए लगातार निगरानी शुरू कर दी है।

शुक्रवार को अधिकारियों के निर्देश पर नायब तहसीलदार सीपी राजपूत मकनपुर पहुंचे। उन्होंने डीएम आवास, मेला गेस्ट हाउस निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर बंधे गाय-भैंसों के खूटों को तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर व आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश भी संबंधित कर्मचारियों को दिए गए। तहसील प्रशासन का कहना है कि बसंत मेले के दौरान श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी

प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त किया जा रहा है। इस दौरान लेखपाल सुनील चौधरी,मेला कमेटी सदस्य नन्द लाल पाल, दीपक श्रीवास्तव,अधिवक्ता कामियाब हुसैन जाफरी, पाशा समेत कई लोग मौजूद रहे।

अपर्णा यादव पर केजीएमयू प्रशासन ने लगाए गंभीर आरोप

» केजीएमयू प्रशासन ने उनके साथ आए लोगों पर अभद्रता, नारेबाजी, तोड़फोड़ और चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए चौक कोतवाली में तहरीर दी

» मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब देर शाम अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके साथ आए लोगों पर अभद्रता, नारेबाजी, तोड़फोड़ और चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए चौक कोतवाली में तहरीर दी है। केजीएमयू के मुख्य प्रॉक्टर की ओर से दी गई तहरीर में मांग की गई है कि पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन का आरोप है कि अपर्णा यादव के साथ आए लोगों ने अस्पताल परिसर में अनुशासनहीनता फैलाते हुए माहौल खराब किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

उधर, इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब देर शाम अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केजीएमयू प्रशासन की ओर से अराजकता की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपर्णा यादव को तलब किया था।अपर्णा यादव की मुलाकात के ठीक बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी मुख्यमंत्री से

मिलने पहुंचीं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। लगातार हो रही उच्चस्तरीय बैठकों ने संकेत दे दिए हैं कि प्रकरण को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है।

फिलहाल केजीएमयू प्रशासन की तहरीर पर पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है,

जबकि पूरा मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

एसडीएम पर लगे जातीय उत्पीड़न के आरोप, जांच में नहीं हुए साबित

एसडीएम आलोक प्रसाद की सुरक्षा में तैनात सवर्ण समाज के 3 होमगार्ड जवानों द्वारा लगाए गए थे गंभीर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बहराइच। महसी तहसील में एसडीएम आलोक प्रसाद की सुरक्षा में तैनात तीन होमगार्ड जवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के बाद प्रशासन ने उन्हें निराधार बताया है। होमगार्ड जवानों ने एसडीएम पर जातिसूचक अपशब्द कहने, शारीरिक उत्पीड़न कराने और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी।

आरोपी एसडीएम आलोक प्रसाद

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित दिव्यांग व्यक्ति, तहसील कर्मचारी और शिकायतकर्ता होमगार्ड जवानों के बयान दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि शिकायतकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस तथ्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते आरोपों को झूठा पाया गया।होमगार्ड जवानों ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि बुधवार को ड्यूटी के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाने पर एसडीएम नाराज हो गए और कथित तौर पर जातिसूचक गालियां दीं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि एसडीएम ने अपने गनर और चालक को जवानों से दौड़ लगवाने और उठक-बैठक कराने के निर्देश दिए तथा उसका फोटो भेजने को कहा। जवानों का कहना था कि इसके बाद उन्हें ड्यूटी स्थल से भगा दिया गया और जान-माल की धमकी भी दी गई।

महसी कंपनी के होमगार्ड आरक्षी राजाराम शुक्ला, रमाकान्त मिश्र और राम कुमार तिवारी वर्तमान में एसडीएम महसी की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं। जवानों ने यह भी आरोप लगाया कि ड्यूटी व्यवस्था में मनमानी के कारण उन्हें 24 से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है।हालांकि प्रशासनिक जांच में इन सभी आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की गई और उपलब्ध साक्ष्यों व बयानों के आधार पर होमगार्ड जवानों के आरोप तथ्यहीन पाए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले को लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।

सीडीओ ने काम न करने वाले तीन कर्मचारियों को किया बर्खास्त

मुख्य विकास अधिकारी ने पीएमएफएमई योजना की समीक्षा बैठक में दिए कई निर्देश

अपात्र आवेदनों की काउंसिलिंग कर एक सप्ताह में निर्णय लेने के दिए आदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में विकास भवन में पीएमएफएमई (क्करूस्नरूश्व) योजना को लेकर बैंकर्स, स्टेकहोल्डर्स एवं डीआरपी की उपस्थिति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने योजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल 1454 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा 442 बैंक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 406 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं।अस्वीकृत आवेदनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 218 प्रस्तावों के सापेक्ष 117, बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा 362 के सापेक्ष 105 तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 179 के सापेक्ष 82 प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए।

इस स्थिति पर मुख्य विकास अधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अस्वीकृत आवेदनों के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कर एक सप्ताह के भीतर तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित बैंकों के साथ आमने-सामने वार्ता कर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अंतिम निर्णय लिया जाए।

जिला उद्यान अधिकारी ने यह भी बताया कि 1030 के लक्ष्य के सापेक्ष 442 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 374 इकाइयों की स्थापना पूर्ण हो चुकी है तथा 65 इकाइयों का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य विकास अधिकारी ने डीआरपीवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अंकित यादव, नेहा देवी एवं राकेश कुमार गुप्ता द्वारा कोई कार्य न किए जाने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं।

साथ ही संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को विकास भवन में कैंप लगाकर आवेदनों की कमियां दूर कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में राकेश कुमार (अग्रणी जिला प्रबंधक), उमेश गुप्ता (जिला कृषि अधिकारी), प्रदीप कुमार (जिला समन्वयक, बड़ौदा यूपी बैंक), अनूप कुमार (भारतीय स्टेट बैंक), अखिलेश कुमार अग्निहोत्री (जिला ग्रामोद्योग अधिकारी) निखा सचान (आजीविका मिशन) सहित अन्य अधिकारी, डीआरपी, पटल सहायक एवं रमेश चंद्र कटियार उपस्थित रहे।

रेल कर्मी आत्महत्या मामला: वीडियो बना वजह, तीन अधिकारियों पर केस

» दुष्प्रेरण व एससी/एसटी एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा, सीओ स्तर से होगी जांच

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव निवासी रेलवे विभाग के सहायक इलेक्ट्रिफिकेशन कर्मी विजय पाल पासवान (45) की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे विभाग के तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आत्महत्या से पूर्व बनाए गए वीडियो को अहम साक्ष्य मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

परिजनों के मुताबिक विजय पाल पासवान ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपने ही विभाग के अवर अभियंता अवश किशोर, अवर अभियंता अविलाश पांडेय और सहयोगी रोहित पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में विजय पाल ने कहा कि उस पर करीब 15 क्विंटल कॉपर तार चोरी का झूठा आरोप लगाकर लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। इसी दबाव के चलते उसे निलंबित भी कर दिया गया, जिससे वह अवसाद में चला गया।

आम के पेड़ से लटका मिला शव

शनिवार सुबह सरवनखेड़ाझूरनिया मार्ग के किनारे आम के पेड़ से विजय पाल का शव मफलर के सहारे फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची गजनेर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

परिजनों का कहना था कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच होती, तो विजय पाल आज जिंदा होता।

08 कानपुर देहात स्वराज इंडिया

संदिग्ध हालात में रेल कर्मी ने दी जान
तीन अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप

पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ केस

मृतक की पत्नी रानी देवी की तहरीर पर गजनेर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और अनुसूचित जाति उत्पीड़न (एससी/एसटी एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

गजनेर थाना प्रभारी ने बताया कि सुसाइड वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर को सौंपी गई है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

इस घटना ने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन विभाग की आंतरिक जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ठोस साक्ष्य के किसी कर्मचारी को निलंबित करना और मानसिक दबाव बनाना गंभीर लापरवाही है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 । **Email:** swarajindia2023@gmail.com । **Mob:** 7800009853, । **Website:** www.swarajindianews.com । **(समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)** प्रादेशिक कार्यालय :4ए/5,119/10बी, खान बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज

नए वोट बढ़ाने को लगाया गया मतदाता शिविर

» मतदाता के साथ माता-पिता के दस्तावेज भी अनिवार्य

» नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को जोड़ने पर फोकस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अब जिले में नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत रसूलाबाद में विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया गया, जहां नए मतदाताओं का पंजीकरण और मतदाता सूची में संशोधन का कार्य किया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर शनिवार को रसूलाबाद कस्बे स्थित आरपीएस इंटर कॉलेज में शिविर लगाया गया। शिविर में सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने नए आवेदन पत्र स्वीकार किए और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन भी किए। इस दौरान खास तौर पर नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर जोर दिया गया।

अब वोट बनवाना नहीं आसान

नगर पंचायत रसूलाबाद क्षेत्र के निर्वाचन सुपरवाइजर लेखपाल रविंद्र कुमार ने बताया कि एसएआर (स्पेशल एब्स्ट्रैक्ट रिवीजन) के बाद अब नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

नए मतदाताओं को फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है, लेकिन अब प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अपना निवास प्रमाण, अंकपत्र या जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता और पिता दोनों के एक-एक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 1987 से 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को स्वयं का एक दस्तावेज और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को केवल अपना एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन्हीं मानकों के आधार पर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

शिविर में बीएलओ के साथ लगाए गए सहायकों ने भी आरपीएस इंटर कॉलेज में बैठकर मतदाता पुनरीक्षण और पंजीकरण का कार्य किया।

मौके पर बीएलओ शैलजा मिश्रा, संजय यादव, ममता देवी, पूनम देवी, गीता देवी, मीना मिश्रा, अनुपम बाजपेई सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान दो बीएलओ मौके से नदारद भी नजर आए, जिसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है।

प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है।

मालगाड़ी की चपेट में आई युवती, आत्महत्या या हादसा

न्यू भाऊपुर-खुर्जा डीएफसीसी ट्रैक पर दर्दनाक घटना, शिनाख्त के प्रयास जारी

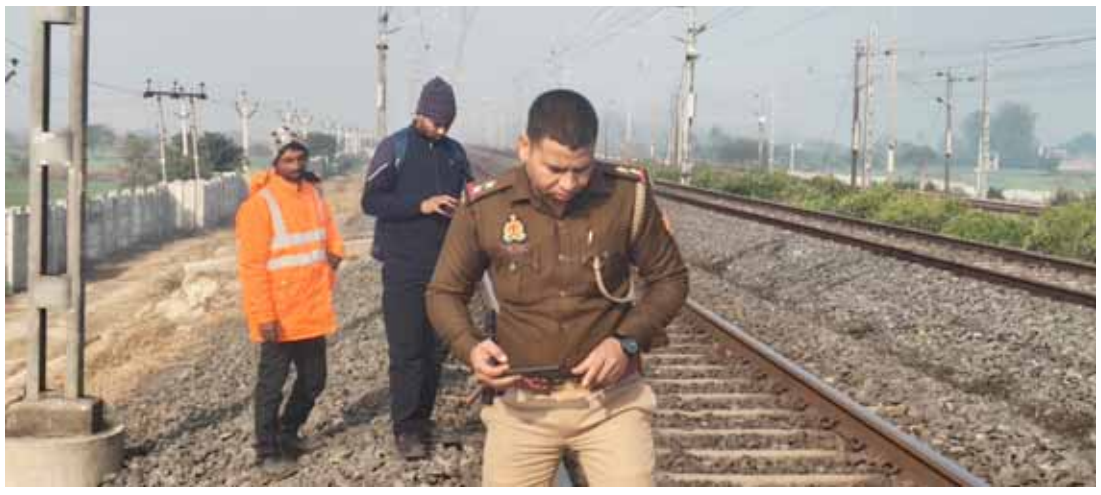

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। न्यू भाऊपुर जंक्शनङ्खखुर्जा डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात युवती की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत झींझक चौकी क्षेत्र में अक्षयवट मंदिर के पास हुई बताई जा रही है। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब साढ़े आठ बजे युवती डीएफसीसी रेलवे ट्रैक के पास मौजूद थी, तभी तेज रफ्तार मालगाड़ी आ गई और वह उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही झींझक चौकी इंचार्ज सुधीर भारद्वाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई पूरी की। मौके से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हो सका है।

पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास आंकी जा रही है। युवती के पहनावे और हुलिए के आधार पर पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।

फिलहाल पुलिस यह स्पष्ट करने में जुटी है कि मामला आत्महत्या का है या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

इसके साथ ही पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों से मिलान कर रही है। मृतका की पहचान के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है।

धान खरीद केन्द्र में किसानों की नियम से हो खरीद

» शिकायत मिलने पर केन्द्र पहुंचे उपजिलाधिकारी, दिए सख्त निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। धान खरीद केंद्र में अनिमितताओं की सूचना पर उपजिलाधिकारी केंद्र पहुंचे। जहां किसानों से संवाद करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से नियमानुसार धान तौल करने की बात कही।

शनिवार को रसूलाबाद तहसील के सामने स्थित धान खरीद केंद्र पर अचानक उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह पहुंच गए और औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से संवाद किया तो कुछ किसानों ने बताया कि धान खरीद में लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर उपजिलाधिकारी सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि किसानों की ही धान खरीदी जाए। इसके साथ ही टोकन के अनुसार ही नंबर के साथ धान की खरीद की जाए। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रकाश में आई तो निश्चित कार्रवाई होगी। इस मौके पर केंद्र प्रभारी तोष्कार झा, बाबू अमित कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान तौल हो रही धान को भी उपजिलाधिकारी ने देखा।

किशोरी लापता, युवक पर फुसलाकर ले जाने का आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद के मंगलपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने एक युवक पर किशोरी को फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़ित पिता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री बीते गुरुवार की शाम लगभग 6 बजे घर से कहीं चली गई थी। तलाश के दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि कन्नौज जनपद के तिर्वा थाना क्षेत्र के मदनापुर गांव निवासी विशाल नामक

युवक उनकी बेटी को फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बताया गया कि आरोपी युवक अक्सर मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने बहनोई के यहां आना-जाना करता था। प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी और आरोपी युवक की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।

जमीन माफिया पर बुलडोज़र का बड़ा प्रहार

» मांझा बरहटा में 450 विश्वा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, रियल एस्टेट सिंडिकेट में हड़कंप

» बिना नक्शा, बिना ले-आउट खुलेआम चल रहा था अवैध निर्माण का खेल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी की पवित्र भूमि पर अवैध प्लाटिंग के काले खेल पर आखिरकार अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) का बुलडोज़र गरज उठा। प्राधिकरण सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मांझा बरहटा में लगभग 450 विश्वा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर जमींदोज़ कर दिया गया। यह कार्रवाई न सिर्फ अवैध निर्माण पर चोट है, बल्कि जमीन माफियाओं के पूरे नेटवर्क के लिए सख्त संदेश भी है।

एडीए सचिव हेम सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में साफ हुआ कि संबंधित भूमि पर न तो कोई स्वीकृत ले-आउट था, न ही मानचित्र की अनुमति इसके बावजूद प्लाट काटकर बेचने की तैयारी पूरी कर ली गई थी।

सूत्रों की मानें तो भोले-भाले लोगों को रामनगरी में सस्ती जमीन का सपना दिखाकर सौदे तय किए जा रहे थे।

कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए रास्ते, सीमांकन और प्लाटिंग के निशान पूरी तरह मिटा दिए गए। स्थानीय स्तर पर सक्रिय रियल एस्टेट दलालों और अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। यह वही नेटवर्क है जो वर्षों से नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति प्लाट काटकर आम लोगों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगाता रहा है।

प्राधिकरण ने दिया साफ संदेश

नियम तोड़े तो कार्रवाई तय एडीए सचिव ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत ले-आउट और मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण या विकास न कराया जाए। केवल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट वाली भूमि का ही क्रय-विक्रय करें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत ले-आउट की सूची एडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे देखे बिना जमीन खरीदना जोखिम भरा हो सकता है।

क्या अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोज़र चलेगा

भोली आस्था, मुनाफे का धंधा रामनगरी में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, आस्था से जुड़ा विषय है। लेकिन इसी आस्था को हथियार बनाकर कुछ लोग अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं नियमों को कुचल रहे हैं और लोगों को कानूनी पचड़ों में फंसा रहे हैं। मांझा बरहटा की कार्रवाई ने यह उजागर कर दिया कि अगर समय रहते कदम न उठाया जाता, तो सैकड़ों लोग ठगी का शिकार हो सकते थे।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? क्या अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोज़र चलेगा? और क्या जमीन माफियाओं के पीछे बैठे सफेदपोश संरक्षक भी जांच के दायरे में आएंगे? यह कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी। जब अवैध प्लाटिंग के पूरे नेटवर्क पर एकसाथ प्रहार किया जाएगा। रामनगरी में अब संदेश साफ है कानून से बड़ा कोई नहीं, और अवैध जमीन का सपना अब महंगा पड़ेगा।

आगरा में शराब ठेके पर 'घूंघट' का धावा, लाठी-डंडों से तोड़ी बोतलें

» घूंघट में पहुंचीं ग्रामीण महिलाएं, लाखों की शराब सड़क नष्ट की

» शराबियों से परेशान महिलाओं का फूटा गुस्सा, पुलिस ने संभाला

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

आगरा।आगरा में शराब के खिलाफ महिलाओं का उग्र और संगठित विरोध सामने आया है। थाना सैंया क्षेत्र के तेहरा चौकी अंतर्गत बिरहरू गांव स्थित देशी शराब के ठेके पर शुक्रवार दोपहर ग्रामीण महिलाओं ने धावा बोल दिया। घूंघट ओढ़े हाथों में लाठी-डंडे लिए महिलाओं ने ठेके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शराब

की पेटियां बाहर निकालकर एक-एक बोतल तोड़ दी।

अचानक हुए इस हमले से ठेके पर मौजूद सेल्समैन मौके से भाग निकले। आक्रोशित महिलाओं ने शराब के साथ ही ठेके पर रखे फ्रिज और अन्य सामान को भी तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया। घटना के दौरान काफी देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। ठेके पर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

सूचना मिलने पर सैंया पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया। बाद में डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। देर शाम तक इस मामले में कोई तहरीर दर्ज नहीं की गई है। ठेका संचालक का दावा है कि इस घटना में करीब पांच लाख रुपये की शराब और अन्य सामान का नुकसान हुआ है।

ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि शराब ठेका रिहायशी इलाके में स्थित है, जहां सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे घर का माहौल खराब हो रहा है और बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ठेके पर आने वाले शराबी अक्सर फब्तियां कसते हैं, जिससे उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को लेकर पहले भी ठेकेदार से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंततः आक्रोशित महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

संघ की पाठशाला से निकले चेहरे और आयातित राजनीति की टकराहट

अयोध्या विधानसभा 2027 : विचारधारा बनाम अवसरवाद

समीर शाही स्वराज इंडिया

अयोध्या। रामनगरी की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले दूर दिखे, लेकिन अयोध्या सीट पर भीतर ही भीतर वैचारिक संघर्ष शुरू हो चुका है। यह संघर्ष सिर्फ चेहरों का नहीं, बल्कि संघड्डविचारधारा बनाम दल-बदल और परिवारवाद की राजनीति का है। अयोध्या लोकसभा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह विद्यार्थी परिषद की उपज हैं। संघ की शाखाओं में तपकर निकले लल्लू सिंह को शुरू से संघ का वरदहस्त प्राप्त रहा। दो बार भाजपा जिलाध्यक्ष पांच बार विधायक (1991, 1993, 1996, 2002, 2007) दो बार सांसद (2014, 2019) करीब 35 वर्षों की वैचारिक राजनीति के बाद भी आज वे जिले में आयातित नेताओं की गुटबाजी से जूझते दिखते हैं। पार्टी से जुड़े लोग मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परोक्ष विरोध और अंदरूनी खींचतान का बड़ा कारण यही गुटबाजी रही।

संगठन में लल्लू सिंह को आज भी बरगद कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है—क्या बरगद की छांव में नई पीढ़ी को जगह मिलेगी?

उनके पुत्र विकास सिंह का विधानसभा कार्यक्रमों में दिखना और स्वयं लल्लू सिंह का 2027 को लेकर सक्रिय होना, इस ओर इशारा करता है कि राजनीति का यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ।

विनय कटियार रामजन्मभूमि आंदोलन की वैचारिक धरोहर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो एक और बड़े संकेत दे रहे हैं।

» लल्लू सिंह- संगठन का बरगद, पर गुटबाजी की आंधी

रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रखर चेहरे, तीन बार लोकसभा सांसद दो बार राज्यसभा सांसद रहे विनय कटियार अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। भाजपा की खांटी वैचारिक उपज विनय कटियार को नजरअंदाज करना संगठन के लिए आसान नहीं होगा।

हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की उनसे मुलाकात को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। यह मुलाकात संकेत देती है कि अयोध्या की वैचारिक धुरी अब फिर से सक्रिय हो रही है।

वही वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता दल-बदल से सत्ता तक का सफर तय कर चुके है। वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का राजनीतिक सफर भाजपा की वैचारिक राजनीति के ठीक उलट दिखाई देता है।

2002 में सपा से चुनाव, तीसरा स्थान 2012 में बसपा से चुनाव, फिर तीसरा स्थान 2017 में भाजपा, मोदीङ्कयोगी लहर में जीत 2022 में पुनः जीत अब 80 वर्ष की उम्र में वे राजनीतिक विरासत को परिवार में सुरक्षित करने की कोशिश में हैं।

पुत्र अमल गुप्ता और बड़े पुत्र विशाल गुप्ता दोनों की सक्रियता चर्चा में है। पार्टी के भीतर यह सवाल गूंज रहा है—

क्या भाजपा विचारधारा की पार्टी...

जबकि अयोध्या नगर निगम के

लल्लू सिंह

प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय संघ का शांत लेकिन मजबूत स्तंभ माना जा रहा।

विद्यार्थी परिषद से निकले, संघ के चहेते और रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या से एक मजबूत वैचारिक दावेदार माने जा रहे हैं।

2017 में नगर निगम का चुनाव सामाजिक कार्यों में निरंतर सक्रियता प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ 2023 में टिकट न मिलने के बावजूद संगठन में उन्हें समायोजित करने का दबाव साफ दिखता है। संघ पृष्ठभूमि के कारण उनका दावा अंदरखाने मजबूत माना जा रहा है। वर्तमान महापौर गिरीश पति त्रिपाठी कांग्रेस से कमल तक का सफर पूरा कर चुके है।

अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी का राजनीतिक सफर भी दिलचस्प है।

कांग्रेस पृष्ठभूमि से निकलकर

महंत गिरीश पति त्रिपाठी महापौर अयोध्या

ऋषिकेश उपाध्याय प्रथम महापौर अयोध्या

वेद प्रकाश गुप्ता विधायक

विनय कटियार

अन्य दावेदार और संगठन की चुनौती

गोसाईगंज से आए इंद्र प्रताप तिवारी 'खब्बू' को समायोजित करने का दबाव भाजपा नेता शक्ति सिंह, अभिषेक मिश्रा भी दावेदारी की कतार में है।ऐसे में अयोध्या सिर्फ सीट नहीं, विचारधारा की परीक्षा अयोध्या विधानसभा अब सिर्फ चुनावी गणित नहीं,यह भाजपा के लिए वैचारिक आत्मपरीक्षा बन चुकी है। सवाल साफ है संघ की पाठशाला में तपे चेहरे आगे बढ़ेंगे, या अवसरवाद और परिवारवाद फिर हावी होगा? रामनगरी का यह चुनाव,भाजपा की राजनीति की दिशा तय करेगा।

2015 में भाजपा का दामन थामना, और 2023 में महापौर बनना इसमें स्मृति ईरानी की भूमिका को पार्टी के लोग खुलकर स्वीकार करते हैं। अब महापौर की कुर्सी के बाद अगली सीढ़ी विधानसभा की ओर उनकी निगाहें हैं।

रामपथ पर बैरिकेडिंग बनी बवाल की वजह, व्यापारियों के विरोध पर फिर रुका काम

मकर सक्रांति मेले में संभावित भीड़ को देखते हुए की गई थी बैरिकेडिंग

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में रामपथ पर निषादराज चौराहे से लता चौक तक डिवाइडर पर लगाई जा रही बैरिकेडिंग एक बार फिर विवाद का कारण बन गई। शुक्रवार को कार्य दोबारा शुरू होते ही स्थानीय व्यापारी भड़क उठे और जबरन काम रुकवाते हुए सड़क पर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सूचना पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्त मौके पर पहुंचे और व्यापारियों का आक्रोश देखते हुए तत्काल कार्य रुकवाया।

विधायक ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित पक्षों की सहमति के बिना बैरिकेडिंग का कार्य नहीं कराया जाएगा,

जिसके बाद व्यापारी शांत हुए। मकर संक्रांति मेले में संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने

रामपथ पर स्थायी बैरिकेडिंग का निर्णय लिया था।

हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इससे शहर और व्यापार दो हिस्सों में बंट जाएगा तथा श्रद्धालुओं, छात्रों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी होगी। व्यापारियों ने स्थायी बैरिकेडिंग के बजाय अस्थायी व्यवस्था करने की मांग उठाई है। फिलहाल विधायक के हस्तक्षेप के बाद कार्य रोक दिया गया है, लेकिन रामपथ पर बैरिकेडिंग का मुद्दा प्रशासन और व्यापारियों के बीच तनाव का कारण

तब तक फांसी पर लटकाया जाए

जब तक उसकी मौत न हो जाए

10 साल के बच्चे की बलि देने वाले चचेरे भाई को फांसी की सजा, दो आरोपी बरी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बहराइच। अंधविश्वास के नाम पर 10 वर्षीय मासूम की नृशंस हत्या के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की अदालत ने नानपारा कोतवाली क्षेत्र के इस जघन्य अपराध में दोषी चचेरे भाई अनूप कुमार वर्मा को फांसी की सजा देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को ÷तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।÷ अदालत ने माना कि आरोपी ने अंधविश्वास में अपने बीमार बेटे को ठीक करने की लालसा में अपने ही चचेरे भाई के बेटे की बलि दी।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी किया था।

नानपारा कोतवाली क्षेत्र के आगैया गांव में 23 मार्च 2023 को राम किशुन के 10 वर्षीय बेटे विवेक वर्मा का क्षत-विक्षत शव खेत में मिला था। घटना के समय विवेक के पिता परिवार के साथ एक निमंत्रण में गए हुए

थे। सूचना मिलते ही वह गांव लौटे और पुलिस को तहरीर दी। शुरुआत में किसी को नामजद नहीं किया गया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने विवेक के सगे चचेरे भाई अनूप कुमार वर्मा, गांव के चिंताराम और बेंचईपुरवा निवासी तांत्रिक जंगली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अनूप ने बताया कि उसका बेटा सत्यम लंबे समय से बीमार था। एक तांत्रिक के कहने पर उसने परिवार के ही किसी बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया।

इसी साजिश के तहत वह विवेक को खेत में पानी देने के बहाने ले गया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। सजा पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अनूप वर्मा को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में चिंताराम और तांत्रिक जंगली को बरी कर दिया गया है।

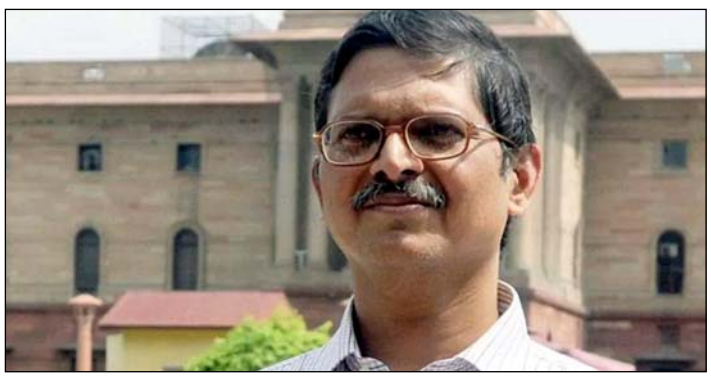

वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर में जिला जज ने दी राहत

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी और आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को वाराणसी की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, इस जमानत के बावजूद अमिताभ ठाकुर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। देवरिया में दर्ज जमीन धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वह वर्तमान में देवरिया जिला कारागार में ही बंद रहेंगे।

मामले की पृष्ठभूमि 30 नवंबर 2024 की एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है। अमिताभ ठाकुर ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर कफ सिरप से जुड़े एक कथित मामले को उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस पोस्ट को लेकर वाराणसी के हिंदू युवा वाहिनी नेता अम्बरीष सिंह उर्फ भोला ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि अमिताभ ठाकुर ने बिना प्रमाण के कफ सिरप प्रकरण में उन पर झूठे आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। इसके बाद 9 दिसंबर को चौक थाना वाराणसी में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में दलील दी कि अमिताभ ठाकुर ने किसी व्यक्ति विशेष पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि देवरिया के मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं हो सकी है।

राउरकेला में 9-सीटर विमान क्रैश, 6 लोग घायल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- पायलट की सूझबूझ से टल गई बहुत बड़ी त्रासदी
- टेकऑफ के 10 किमी बाद खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
- तकनीकी खराबी की आशंका, विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त

राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। रघुनाथपाली थाना क्षेत्र के जलदा-ए ब्लॉक के पास वन एयर का एक 9-सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त विमान में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें चार यात्री और दो क्रू मेंबर शामिल थे। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह विमान राउरकेला से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, टेकऑफ के लगभग 10 किलोमीटर बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। पायलट को जैसे ही सिस्टम में गड़बड़ी का एहसास हुआ, उन्होंने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए विमान को एक खेत में क्रैश लैंडिंग कराने का निर्णय लिया। इस दौरान विमान पेट के बल जमीन पर उतरा, जिससे उसकी नाक और अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

दुर्घटना में पायलट समेत सभी यात्रियों को चोटें आई हैं, हालांकि किसी की हालत फिलहाल गंभीर नहीं बताई जा रही है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में घायल यात्री जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद स्थानीय लोग उनकी मदद करते नजर आए।

बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BPIA) प्रशासन ने क्रैश लैंडिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि तकनीकी खराबी सामने आते ही पायलट ने नजदीक मौजूद घास के मैदान को देखकर विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश की, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई। विमान को कैप्टन नवीन और कैप्टन श्रीवास्तव उड़ा रहे थे, दोनों इस हादसे में घायल हुए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। प्रशासन ने क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है।